

New govt should create 80L jobs in 5 yrs: Assocham

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: ASSOCHAM (The Associated Chambers of Commerce and Industry of India) released a report named 'Action Agenda for the new government of UP' that suggests UP should focus on growth of small and medium enterprises (SMEs) and start-ups to help create about 80 lakh new jobs in next five years. The association submitted this pre-election agenda to leaders of major political parties in UP to include in their election manifesto.

The report pointed out that UP's economic growth not only surpassed India's economic growth in last financial year, its contribu-

tion to India's economy has shown consistent improvement owing to stability in economic activities during the tenure of the present regime. "UP's contribution to India's economy had declined from 8.78% in 2004-05 to 7.97% in 2011-12, but thereafter it picked up gradually to reach 8.16% in 2014-15," the agenda highlights.

The chamber's secretary general D S Rawat said, "Assocham Special Task Force on UP has formulated a 'Sustainable Action Plan' to achieve double-digit growth in the state in next five years." UP should aim to sustain current level of workforce participation rate of about 33% for working age group of 15-30 years.

Assocham presents industries' agenda to political parties

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

LUCKNOW: The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (Assocham) presented pre-election agenda to all leading political parties on Thursday to incorporate in their election manifesto and urged them to lay stress on small and medium enterprises and startups that can help create 80 lakh new jobs in the next five years.

"The Assocham special task force on Uttar Pradesh has formulated a 'sustainable action plan' to achieve double digit growth in the state in next five years to help the state enter the 'high income club of states'," said DS Rawat, secretary general of the organisation. The Assocham has also suggested to promote non-crop activities like animal husbandry, dairying, fisheries, floriculture, horticulture and poultry to create new employment opportunities.

The industrialists' body also recommended effective implementation of projects by the government. Assocham also listed out some suggestions for political parties, like identifying potential areas for setting up special economic zones (SEZs) along with ensuring single window clearance related facilities and technological modernisation.

Agriculture and allied activities contribute about 13% to India's agriculture sector and 22% to UP's economy. It also

AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES CONTRIBUTE ABOUT 13% TO INDIA'S AGRICULTURE SECTOR AND 22% TO UP'S ECONOMY. IT ALSO EMPLOYS ALMOST 67% OF THE STATE'S TOTAL WORKFORCE.

employs almost 67% of the state's total workforce. Assocham has suggested that the new state government should focus on accelerating agricultural productivity by promoting cluster farming, providing good quality seeds, promote biotech crops to improve yield, push organic farming and offer sops for setting up food processing industries.

Though industrial sector contributes about 20% to UP's economy and just about seven percent to India's industry, poor infrastructure together with non-availability of land are major bottlenecks restricting new industries from being set up in the state which is also directly impacting employment generation.

The Assocham agenda highlighted that developing infrastructure like roads, ensuring consistent power supply, and up-skilling micro, small and medium enterprises workers were key thrust areas for industrial sector development in the state.

‘Tech platform for SMEs to create 80 lakh jobs in UP’

Lucknow (PNS): With thrust on creating a technology platform for growth and development of small and medium enterprises (SMEs) and startups, Uttar Pradesh (UP) should aim to create about 80 lakh new jobs in next five years, noted an ASSOCHAM agenda for inclusion in election manifesto of political parties in fray for upcoming assembly polls.

“UP has recorded impressive economic growth during the course of past few years, the state holds significant potential to become front-runner if it carries on with the momentum and is able to attain double digit growth during next five years,” noted the ASSOCHAM pre-election agenda which has been submitted to leaders of major political parties.

It should also be noted that UP’s economic growth not only surpassed India’s economic growth in FY15 but the state’s contribution to India’s economy has shown consistent improvement owing to stability in economic

activities during the tenure of the present regime. UP’s contribution to India’s economy had declined from 8.78 per cent in 2004-05 to 7.97 per cent in 2011-12, but thereafter it picked up gradually to reach 8.16 per cent in 2014-15.

“ASSOCHAM Special Task Force on Uttar Pradesh has formulated a ‘Sustainable Action Plan,’ to achieve double digit growth in the state in next five years to help UP enter the ‘high income club of states,’” said the chamber’s secretary general DS Rawat. * UP should aim to sustain current level of workforce participation rate of about 33 per cent for working age group of 15-30 years, about 1.40 crore people are already a part of the workforce.

Promoting non-crop activities like animal husbandry, dairying, fisheries, floriculture, horticulture and poultry to create new employment opportunities, strengthening self-employment and entrepreneurship development programs, ensuring adequate and timely supply of credit at reasonable cost together with reforming existing labour laws are certain key suggestions to shore up employment scenario in UP.

Though UP attracted outstanding investments worth about Rs nine lakh crore registering compounded annual growth rate (CAGR) of over 23 per cent during the nine year period between 2006-07 and 2015-16, ensuring effective implementation should be the key priority of the new state government.

हमारे सुझावों को वादों में शामिल करें पार्टियां : एसोचैम

■ लखनऊ

उद्योग मंडल एसोचैम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रमुख पार्टियों को अपने घोषणापत्र में शामिल करने के लिए विकास से सम्बन्धित सुझाव दिए हैं।

एसोचैम ने राज्य के विकास की सम्भावनाओं का गहन आकलन करके एक परामर्श एजेंडा के तहत कुछ वादे सुझाए हैं। उसका कहना है कि अगर राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणापत्र में इन सुझावों को वादों के तौर पर शामिल करें तो वे न सिर्फ जनता को तरक्की की नई उम्मीद दे सकती हैं, बल्कि सत्ता में आने पर उन्हें एक फलदाई दिशा भी मिल सकती है।

दोहरे अंकों में विकास दर : एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव डीएस रावत ने यहां एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर संगठन की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कार्ययोजना बनाई है, ताकि इस प्रदेश को अगले पांच साल में दोहरे अंकों में विकास दर प्राप्त करने और उच्च आय वाले राज्यों के क्लब में शामिल होने में मदद मिल सके।

80 लाख नए रोजगार के अवसर : उद्योग मंडल ने सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश में लघु तथा मझोले उद्योगों (एसएमई) तथा स्टार्टअप के लिए प्रौद्योगिकीय मंच तैयार करने पर जोर देकर अगले पांच साल में रोजगार के 80 लाख नए अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य तय किया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही सभी प्रमुख पार्टियों के नेताओं को सौंपे गए एसोचैम के एजेंडा में कहा गया है, 'उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रभावशाली आर्थिक विकास हासिल किया है। इस राज्य में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की क्षमता है, बशर्ते वह अपनी गति को बनाए रखे और अगले पांच साल के दौरान विकास दर को दोहरे अंकों में पहुंचाए।' यह ध्यान देने योग्य बात है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जहां यूपी की आर्थिक विकास दर देश की विकास दर से ज्यादा थी।

देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान बढ़ा : एसोचैम के एजेंडा में रेखांकित किया गया है कि वर्ष 2011-12 में देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 2004-05 के 8.78 प्रतिशत के मुकाबले गिरकर 7.97 प्रतिशत हो गया था, लेकिन बाद में इसने गति पकड़ी और यह वर्ष 2014-15 में बढ़कर 8.16 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। संगठन ने सुझाव दिया है कि प्रदेश में रोजगार का परिदृश्य तैयार करने, स्वरोजगार तथा

एसोचैम के सुझाव

■ "उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रभावशाली आर्थिक विकास हासिल किया है। इस राज्य में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की क्षमता है, बशर्ते वह अपनी गति को बनाए रखे और अगले पांच साल के दौरान विकास दर को दोहरे अंकों में पहुंचाए।"

कृषि उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना होगा

एसोचैम ने सुझाव दिया है कि प्रदेश की नई सरकार को राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए उसे संकुल खेती (क्लस्टर फार्मिंग) को बढ़ावा देने, अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने, उपज में सुधार के लिए बायोटेक फसलों को बढ़ावा देने, आर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने, फसल उत्पादन के बाद बाजार उपलब्ध कराने की ठोस नीति बनाकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और सिंचाई क्षेत्र द्वारा आकर्षित निवेश प्रस्तावों का प्रभावी क्रियान्वयन करने की जरूरत होगी। कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्र का देश के कृषि क्षेत्र में करीब 13 प्रतिशत का योगदान है जबकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 22 प्रतिशत है। इसके अलावा प्रदेश की लगभग 67 प्रतिशत जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र पर ही निर्भर करती है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए गैर-फसली काम, जैसे कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य कारोबार, फूलों की खेती, बागवानी तथा कुक्कुट पालन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित करने होंगे।

घोषणा पत्र में दल ढांचागत विकास को शामिल करें : एजेंडा में कहा गया है कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सड़क रूपी ढांचा विकसित करना, बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, कर्मियों को प्रशिक्षण देना, विशेषीकृत एवं परम्परागत उद्योगों का संकुल के रूप में विकास करना, कृषि-उद्योग सहलग्नता को मजबूत करना और एमएसएमई के कामगारों की क्षमता का विकास करना इत्यादि प्रमुख कार्य हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्र में शामिल करना चाहिए। ■ भाषा



उद्योगों व खेती को घोषणा पत्र में मिले प्राथमिकता

लखनऊ (ब्यूरो)। एसोचैम का सुझाव है कि खेती और उद्योगों को अपने घोषणा पत्र में प्राथमिकता देकर राजनीतिक दल प्रदेश के विकास की धारा तैय कर सकते हैं। लघु और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप को इसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। उद्योग संगठन ने पार्टियों से कई बिंदुओं पर अपेक्षा जताते हुए इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है।

संगठन का कहना है कि बीते कुछ सालों में प्रदेश में जो आर्थिक विकास देखने को मिला है वह बेहद प्रभावशाली है। विकास का यही क्रम जारी रहे तो अगले पांच वर्षों में यूपी की विकास दर दो अंकों में पहुंच सकती है। यूपी में हुए विकास का असर देश की विकास दर पर भी

एसोचैम ने राजनीतिक दलों के लिए जारी किए कुछ सुझाव

देखने को मिल रहा है। वर्ष 2014-15 में देश 8.16 प्रतिशत की विकास दर यूपी के बल पर ही हासिल करना संभव हो सका था। क्योंकि प्रदेश की विकास दर इससे कहीं अधिक थी। एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव डीएस रावत का कहना है कि एसोचैम की स्पेशल टास्क फोर्स ने यूपी के विकास को ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके जरिए यूपी को देश के टॉप राज्यों में शामिल कराया जा सकता है। इसी सिलसिले में राजनीतिक दलों के लिए घोषणा पत्र के संबंध में कुछ सुझाव जारी किए गए हैं।

एक्शन प्लान में खास

प्रदेश के 15 से 30 आयु वर्ग की करीब 33 प्रतिशत वर्क फोर्स को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जाएं।

पशुपालन, डेयरी, मत्स्य कारोबार, फूलों की खेती, बागवानी तथा मुर्गी पालन को बढ़ावा मिले जिससे रोजगार बढ़ेगा।

किसानों और स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक लोगों को सस्ती दर पर कर्ज की उपलब्ध करवाया जाए।

देश की अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि क्षेत्र 13 प्रतिशत का योगदान करता है, जबकि यूपी में 22 प्रतिशत, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देकर वलन्टर फार्मिंग को बढ़ाने, गुणवत्ता के बीज मुहैया कराने,

बायोटेक्नोलॉजी के साथ-साथ ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने पर विचार होना चाहिए।

यूपी की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का करीब 20 प्रतिशत योगदान है और भारत में केवल सात प्रतिशत, इसके बावजूद नए उद्योगों के विकास के लिए काफी सुधार किए जा सकते हैं। जिन्हें लागू किया जाना चाहिए।

यूपी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सर्विस सेक्टर 58 प्रतिशत योगदान दे रहा है। ऐसे में ई-गवर्नेंस बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में सुधार करना होगा ताकि, यह योगदान बना रहे।

